



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 27 दिसम्बर, 2006/6 पौष, 1928

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-2, 27 दिसम्बर, 2006

संख्या वि० स०-विधायन-गवर्नमेंट बिल/1-60/2006.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की

प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन)

2922-राजपत्र/2006-27-12-2006—1,437.

(9187)

मूल्य: एक रुपया।

विधेयक, 2006 (2006 का विधेयक संख्यांक 28) जो आज दिनांक 27 दिसम्बर, 2006 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

जे० आर० गाज़टा,
सचिव।

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2006

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2006 है ।

संक्षिप्त
नाम और
प्रारम्भ।

(2) यह 16 नवम्बर, 2006 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

1994 का 12 2. हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 में, विद्यमान खण्ड(14)के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:--

धारा 2 का
संशोधन ।

“(14) ‘मण्डलायुक्त’ से उस मण्डल का आयुक्त अभिप्रेत है जिसमें निगम स्थित है और इस अधिनियम के अधीन मण्डलायुक्त के सभी या उनमें से किसी कृत्य के पालन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य अधिकारी इसके अन्तर्गत है;”।

3. मूल अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (2) में विद्यमान खण्ड (थ) का परन्तुक सहित लोप किया जाएगा।

धारा 8 का
संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (1) में “राजस्व आयुक्त” शब्दों के स्थान पर “मण्डलायुक्त” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 14 का
संशोधन।

5. (1) हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2006 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है ।

2006 के
अध्यादेश
संख्यांक 5 का
निरसन और
व्यावृत्ति ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य में राजस्व आयुक्त के पद को समाप्त किए जाने के परिणामस्वरूप राजस्व आयुक्त के कृत्यों को हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी को सौंपना आवश्यक हो गया था। इसलिए यह विनिश्चय किया गया कि राजस्व आयुक्त के कृत्यों को पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन मण्डलायुक्त द्वारा किया जाना चाहिए। वर्तमान में शिमला नगर निगम के वार्डों के प्रस्तावित परिसीमन के विरुद्ध प्राप्त लोक आक्षेपों पर उपायुक्त द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध संस्थित अपीलों की सुनवाई राजस्व आयुक्त द्वारा, अपीली प्राधिकारी होने के नाते, की जा रही है जबकि यह पद समाप्त हो चुका है। अतः हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 2 में पारिणामिक संशोधन किया जाना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त, नगर निगम से अन्यथा, नगरपालिकाओं के निर्वाचन में दो बच्चों के मानदण्ड वाले उपबन्ध का लोप पहले ही किया जा चुका है क्योंकि इस उपबन्ध से सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो गईं तथा इसकी महिला-विरोधी उपबन्ध के रूप में आलोचना की गई थी, इसलिए इस उपबन्ध को पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 8 से हटाए जाने का विनिश्चय किया गया था। इसके अतिरिक्त नगर निगम के पार्षद के चुनाव से सम्बन्धित निर्वाचन याचिकाएं हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 14 के अधीन राजस्व आयुक्त को प्रस्तुत की जाती हैं परन्तु राजस्व आयुक्त के पद को समाप्त किए जाने से उपरोक्त अधिनियम की धारा 14 में पारिणामिक संशोधन किया जाना अपेक्षित था।

क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 12) में तुरन्त संशोधन करना आवश्यक हो गया था, इसलिए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2006 (2006 का अध्यादेश संख्यांक 5) 15 नवम्बर, 2006 को प्रख्यापित किया गया था और इसे 16 नवम्बर, 2006 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशित किया गया था। अब उक्त अध्यादेश को नियमित अधिनियमिति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को बिना किसी उपान्तरण के प्रतिस्थापित करने के लिए है।

कौल सिंह ठाकुर,
प्रभारी मन्त्री।

शिमला:

तारीख:

वित्तीय ज्ञापन

--शून्य--

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

--शून्य--

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2006

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

कौल सिंह ठाकुर,
प्रभारी मन्त्री।

डा० जे० एन० बारोवालिया,
सचिव (विधि) ।

शिमला:
तारीख:

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 2006

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 12 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-seventh Year of the Republic of India, as follows :—

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Act, 2006.

Short title
and commen-
cement.

(2) It shall be deemed to have come into force on 16th day of November, 2006.

2. In section 2 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (hereinafter referred to as the "principal Act"), for existing clause (14), the following clause shall be substituted, namely :—

Amendment
of section
2.

"(14) 'Divisional Commissioner' means the Commissioner of the Division in which the Corporation is situated and includes any other officer appointed by the Government to perform all or any of the functions of the Divisional Commissioner under this Act."

3. In section 8 of the principal Act, in sub-section (2), the existing clause (q) alongwith proviso shall be deleted.

Amendment
of section 8.

4. In section 14 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "Revenue Commissioner", the words "Divisional Commissioner" shall be substituted.

Amendment
of section 14.

5. (1) The Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2006 is hereby repealed.

Repeal of
Ordinance
No. 5 of
2006 and
saving.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

As a result of abolition of the post of Revenue Commissioner in the State, it has become necessary to assign the functions of the Revenue Commissioner under the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 to some other Authority. Thus, it was decided that the functions of Revenue Commissioner should be performed by the Divisional Commissioner under the Act *ibid*. At present the appeals instituted against the orders of Deputy Commissioner passed on public objections received against proposed delimitation of wards of the Muninipal Corporation, Shimla, are heard by the Revenue Commissioner, being an Appellate Authority, whereas this post stand abolished. As such, consequential amendment was required to be carried out in section 2 of the Himachal Pradesh Municipal Coporation Act, 1994. Further, the provision of two child norm to the election of municipalities, other than Municipal Corporation, has already been deleted becuase this provision has created social problems and has been criticized as an anti-women provision, thus, it was decided to delete this provision from section 8 of the Act *ibid*. Further, the election petitions relating to the election of a Councillor of the Municipal Corporation are presented to Revenue Commissioner under section 14 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994, but with the abolition of the post of Revenue Commissioner, consequential amendment was also required to be carried out in section 14 of the Act *ibid*.

Since the Himachal Pradesh Legislative Assembly was not in session and the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 12 of 1994) had to be amended urgently, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers under clause (1) of Article 213 of the Constitution of India promulgated the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2006 (Ordinance No. 5 of 2006) on 15th day of November, 2006 and the same was published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) on 16th day of November, 2006. Now, the said Ordinance is required to be replaced by a regular enactment.

This Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance without any modification.

KAUL SINGH THAKUR,
Minister-in-charge.

SHIMLA :

Dated :, 2006.

FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

**THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION
(AMENDMENT) BILL, 2006**

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 12 of 1994).

KAUL SINGH THAKUR,
Minister-in charge.

Dr. J. N. BAROWALIA,
Secretary (Law).

SHIMLA :

The....., 2006.